‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 जुलाई, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 16 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 जुलाई, 2014

हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाये।

&xkre cq)

हैदराबाद में परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज का सांसद बनने पर भव्य स्वागत समारोह एवं राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

विनोद कुमार

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष, श्री के. महेश्वर राज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज को लोक सभा सांसद बनने पर हैदराबाद में 6 जुलाई, 2014 को स्वागत समारोह एवं परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा जिसे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. उदित राज ने सहर्ष स्वीकार करते हुए के. महेश्वर राज को सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कुछ दिशा–निर्देश दिए। के. महेश्वर राज ने माननीय डॉ. उदित राज के दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए सम्मेलन एवं स्वागत समारोह को सफल बनाने के लिए आंध्रप्रदेश की इकाई के साथ तालमेल बनाते हुए पूरे देश से परिसंघ के पदाधिकारियों को आमंत्रित करने एवं संसाधन जुटाने का कार्य बड़े जोश से शुरू किया। जैसे–जैसे पूरे देश में परिसंघ के पदाधिकारियों को मालुम हुआ कि परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. उदित राज का स्वागत समारोह एवं राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद में 6 जुलाई को होने जा रहा है तो परिसंघ के पदाधिकारियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अपने नेता का स्वागत करने एवं राष्ट्रीय सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए के. महेश्वर राज को अग्रिम सूचना देकर कार्य को आसान बनाया और इससे महेश्वर राज के कार्य करने की क्षमता दस गुणा बढ़ गयी।

परिसंघ का कार्यक्रम 6 जुलाई, 2014 को रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में सुबह 9 बजे से शुरू होना था लेकिन अपने नेता का स्वागत करने के लिए लोगों ने 5 जुलाई को ही पूरे देश से हैदराबाद में पहुंचना शुरू कर दिया

अपने प्रतिष्ठित एवं नवनिर्वाचित सांसद डॉ. उदित राज को ध्यानपुर्वक सुनती अपार जनसमर्थक - राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अपार भीड़ को संबोधित करते हुए डॉ. उदित राज

मंच पर (दांये से बांये) जग जीवन प्रसाद, महा सिंह भुरानिया, ब्रह्म प्रकाश, डॉ. अंजु काजल, डॉ. उदित राज,(बीच में), के. महेश्वर राज, विनोद कुमार, परमहंस प्रसाद, सत्य प्रकाश जरावता, इ. बी. राजु, सतीश ढ़ोगड़ा, श्री निवासुलू, संजय राज एवं अन्य

और सुबह 7 बजे से ही ऑडिटोरियम की ओर कूच कर गए। देखते ही देखते सुबह 9 बजे तक पूरा हॉल भर गया और जैसे–जैसे समय बीतता गया वैसे–वैसे लोगों का जमावड़ा भी बढ़ता गया। हालात यह बन गये कि जितने लोग हॉल के अंदर थे उसके चार गुणा लोग हॉल के गैलरी और बाहर अपने राष्ट्रीय नेता उदित राज की एक झलक पाने के लिए एलईडी पर भी देखने को लालायित थे। डॉ. उदित राज सुबह 8:30 बजे सीधे मुंबई से हैदराबाद पहुंचकर रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में 10:15 बजे दाखिल हुए। जैसे ही लोगों को आभास हुआ कि हमारे प्रिय नेता डॉ. उदित राज कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और लोग हाथों में फुलों की माला एवं गुलदस्ते लेकर

शेष पृष्ठ 3 पर...

बिहार में सृजनात्मक गद्य लेखन की विडंबनाएं

(संदर्भ : मंडल आंदोलन का धवल और स्याह पक्ष)

अरुण नारायण

सामाजिक न्याय और उस भाव-भूमि से आनेवाले सभी तरह के विचारों व व्यक्तियों के प्रति हिंदी लेखन की मुख्यधारा और इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया सभी के सभी अपादमस्तक जातीय दुराग्रह से पीड़ित रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि जिस आरक्षण पर लगभग सभी राजनीतिक दलों में स्वाभाविक सर्वानुमति है, वहीं साहित्य में एक हिकारत का भाव है। इस अंदाज में कि यह सीधे-सीधे दूसरे की हकमारी ही है उनकी नजर में। इससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि शाश्वत कहे जाने की दुहाई दिया जाने वाला हमारा साहित्य कहां खड़ा है? और उसकी बागडोर अंततः किस तरह की संकीर्ण शक्तियों के हाथों में है।

बिहार के लेखन की कुछ बानगियों के सहारे मंडल के प्रति उनके नजरिए क्या रहे हैं, इस विषय में आपसे कुछ कहना चाहूंगा। चूंकि मंडल भारतीय इतिहास का ऐसा कालखंड रहा है जिसने भारतीय जनमानस को कई रूपों में उद्वेलित करने का काम किया इसलिए भारतीय मीडिया ने उसे देश को जोड़ने वाली नहीं बल्कि तोड़ने वाली घटना के रूप में चित्रित किया। इतिहास के उस कालखंड को बिहार के उपन्यासकारों और नवजागरणकारों ने भी अपने लेखन का हिस्सा बनाया और उस मीडिया के स्टैंड का ही मुखर समर्थन किया। यह एक ऐसा काल था जिसने बहुजन समाज को पहली बार अपने अधिकारों के प्रति गोलबंद किया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में द्विज जातियों की जो अघोषित किलेबंदी थी वह इस काल में ध्वस्त होनी शुरू हुई। कर्मंडल की भगवाधारी शक्तियों की रीढ़ इसी मंडल ने तोड़ी। लेकिन बिहार के लेखकों को पढ़ें तो हमें मंडल के बारे में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें ही देखने को मिलती हैं। यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरे निहितार्थ हैं? इसके कारणों को संबंधित लेखकों के उद्धरण के साथ ही जानें तो तस्वीर ज्यादा स्पष्ट होगी।

कर्मेन्दु शिशिर खुद को रामविलास शर्मा स्कूल के नवजागरण अध्येता मानते हैं। मतवाला मंडल से लेकर 'सारसुधानिधि' का संपादन, राधामोहन गोकुल व सत्यभक्त की जीवनी के अतिरिक्त दो कहानी संकलन, एक उपन्यास, चार-पांच लेख संकलन व विदेश यात्राओं का भारी-भरकम प्रोफाइल है इनका। पेशे से प्राध्यापक हैं। मंडल दौर को पहले भी कई जगहों पर उन्होंने 'जंगलराज' का पर्याय बतलाया। अपने एक लेख 'बिहार में नवजागरण की विडंबनाएं' में वे लिखते हैं : 'वस्तुतः त्रिवेणी संघ एक नई किसान संस्कृति को मूर्त करने वाला एक अभिनव उपक्रम था। सवर्ण स्वार्थ के वशीभूत ताकतों ने उसे जिस अनैतिक और अविचारित तरीके से रौंदा उसी का कुफ ल आगे चलकर कबिलाई सत्ता के अभिशाप के रूप में बिहार को भुगतना पड़ा।' अपने समय में त्रिवेणी संघ को देवव्रत शास्त्री ने देश को तोड़ने वाला संकीर्ण अवसरवादी संघ कहा था। लेकिन जब उस संघ के बारे में रिसर्च सामने आए तो उन्हीं की आधुनिक जमातें उसकी प्रशंसा में कसीदे काढ़ने नहीं अघाईं। लेकिन अपने वर्तमान में मंडल का 1990 का काल जिन कारणों से महत्व का अधिकारी होता उसकी अनदेखी कर उसे 'कबिलाई सत्ता के अभिशाप' के रूप में व्याख्यायित करना बतलाता है कि सवर्णों के श्रेष्ठताबोध ने मंडल शासन के इस उभार को कभी बर्दाश्त नहीं किया। कर्मेन्दु शिशिर के इस उद्धरण का अर्थ स्पष्ट है। मतलब साफ है कि इनके इस नवजागरण में अतीत के त्रिवेणी संघ जैसे संगठनों के लिए तो बहुत आदर है, लेकिन वर्तमान मंडल जहां से देश और खासकर बिहार की राजनीति में पहली बार बहुजन आबादी की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई वह उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। मंडल उभार के इस काल को 'कबिलाई सत्ता के अभिशाप' के रूप में देखने की वकालत करने वाले शिशिर इसके कारणों में नहीं जाते। ले-देकर इनके पास भी ऐसा कहने के लिए भ्रष्टाचार, अपराध की बढ़ती हुई दर जैसे ही तर्क हैं, जो आम सवर्ण मीडिया का रहा है। शिशिर अपने लेख में यह नहीं बतलाते कि मंडल के जिस काल में अपराध का इतना बोलबाला था वह भारत के दूसरे राज्यों से कैसे ज्यादा था या परवर्ती शासन के आंकड़े कहां उससे भिन्न रहे हैं ?

शिशिर के इस लेख से बहुजन आबादी के साथ ही स्त्री विरोध की कुंठित मानसिकता का भी पता चलता है। जाहिर है जो बहुसंख्यक विरोधी होगा वह स्त्री विरोधी भी होगा ही। देखें इसकी एक बानगी-'वाह मेरे यार! हिटलर के शहर में प्रेम रोपने का अद्भुत सत्कर्म कर तुमने सच्ची भारतीयता का परिचय दिया....लो, हम भी घूम आए।' यह उद्धरण स्त्री विरोधी सामंती कुत्सा का चरम है। 'प्रेम रोपने' शब्द में ब्लंठ सामंती पुरुषवादी कुत्सा का चरम है। शंभुनाथ ने लिखा है, 'यौन तृप्ति सेक्स पाप नहीं है और जीवन में इसकी पूर्ति ठीक ढंग से नहीं होगी, तो विकृतियां पैदा होंगी। शिशिर अपने इस उद्धरण में इस विकृति में आकंठ डूबे हुए हैं। प्रगतिशीलता और पिछड़ावाद की वे जितनी दुहाई दें लेकिन यह सच है कि उनके अंदर से पुरुषवाद और जातीय श्रेष्ठताबोध अभी गया नहीं है।

दूसरे लेखक हैं रमेशचंद्र सिन्हा। अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं। इनके 'इलियड' और 'ओडिसी' के हिंदी अनुवाद की बड़ी ख्याति रही है। अपने पहले उपन्यास 'काक द्वीपय सोमा चरित' के लिए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् का सम्मान इन्हें मिल चुका है। इनके उपन्यास 'अभय कथा' में आजादी पूर्व से लेकर मंडल तक के समय का रेखांकन किया गया है। मंडल के समय के बारे में वे लिखते हैं :'...गाय थी कि इधर-उधर तेजी से भागकर पकड़ में नहीं आ रही थी बल्कि नजदीक जाने पर हुड़पेटती थी। यह देख चीफ मिनिस्टर चिल्लाकर बोला, 'बिना अक्किल के एकदम फालतू आदमी हो, मंगल भगत। एक गऊ को भी नहीं सरिया सकते। तुम्हारा अइसन बोका को बेकारे मंत्री बनाए हैं।' तब उसने हांक लगाई, 'डीजी साहेब! कहां गया साला डीजी? मर तो नहीं गया? अरे अहमदवा, तनिका लपक के देखो कि डीजी सहेबवा कहां लापता हो गया।' तब देखा कि पुलिसवर्दी में एक मोटा-झोंटा आदमी हाथ में काली रूल लिए उस मरखंडी गाय को पकड़ने बंगले से दौड़ता हुआ निकला। उसे देखते ही गाय का पारा और चढ़ गया और वह डीजीपी साहेब को ही खदेड़ने लगी। बेचारा जान लेकर भागा। इस पर चीफ मिनिस्टर ठठाकर हंसा और बोला, 'देखा, चीफ मिनिस्टर का गऊ है कि ठठ्ठा! साले डीजी का हवा गुम कर दिया। ई ससुराली गऊ है। मेम साहब अपने कर से इसको किसमिस और मिसरीकंद खिलाती हैं। एह खातिर इसको मेरा सलवे ठीक करेगा।' स्पष्टतः यह प्रसंग द्विज कुंठा की उस शातिराना एप्रोच की कलई खोलता है जो हमेशा श्रेष्ठताबोध में जीने का अभ्यासी रहा है और जिसके लिए वामपंथ की कलगी प्रगतिशीलता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट साबित हुई है। मंडल के दौर में लालू के सत्तासीन होने के बाद यहां का द्विज नेतृत्व यही प्रचारित करता था कि गाय-भैंस चराने वाला बिहार का शासन नहीं चला पाएगा। लेकिन लालू ने इन तमाम भविष्यवाणियों पर न सिर्फ पलीता लगाया अपितु सत्ता में दलित-पिछड़े को भागीदार बनाया। भगवतिया जैसी हाशिए की मजदूरिन भी बिहार की सत्ता में हिस्सेदार बनीं। सवाल उठता है कि जो लेखक किसी काल का धवल पक्ष नहीं देख सकता वह सही अर्थों में उसका स्याह भी वस्तुनिष्ठ होकर नहीं आंक सकता।

सिन्हा के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यही रही है। सच तो यह है कि 1990 के बाद के बिहारी समाज को देखने के लिए जिस तरह की नजर और संवेदना चाहिए वह बिहार के इन कथित वाम लेखकों के पास है ही नहीं। जातीय व्यवस्था बड़ी उत्पीड़नकारी रही है। इसके पहले सत्ता और संसाधन पर कुछ खास जातियों का वर्चस्व रहा। मंडल ने इस एकाधिकार को तोड़ा। लेकिन बिहार के द्विज लेखकों ने इसे कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया इसलिए 90 के उस काल को वे बिहार के सबसे अंधकारमय काल के रूप में पिरोते रहे हैं। यह जाति व्यवस्था तभी खत्म होगी जब उनका संबंध समानता और सम्मान पर आधारित हो। मंडल ने इसकी कोशिश की तो इन लेखकों का यह दायित्व था कि उसके इस धवल पक्ष को रेखांकित करते, क्योंकि मंडल इस जाति व्यवस्था के खिलाफ वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था उन संघर्षों में मिल का पत्थर है। लेकिन बिहार के द्विज लेखकों ने इस ऐतिहासिक उभार को जैसे बदनाम करने का संकल्प ही ले लिया है। लालू के आरंभिक 5 सालों के कार्यकलापों को देखें तो वे एक बड़े विजनरी के तौर पर उभरते हैं तब आज की तरह रणचंडी पाठ, वंशवाद और सोनिया के पीछे चिपके मदारी नहीं हुए थे वे। उन्होंने तब पूरी गवर्नेंस को जाति व्यवस्था के खिलाफ लगा दिया था। 90 के पहले बिहार की बहुजन आबादी जाति व्यवस्था में घुटन महसूस कर रही थी। ऐसे में उस पर करारा चोट इतिहास की जरूरत थी जिसका निवर्हन लालू प्रसाद ने किया। अक्सर गवर्नेंस की कसौटी पर इस शासन की विफलता को रेखांकित किया जाता है। गवर्नेंस के लिहाज से लालू प्रसाद ही क्यों श्रीकृष्ण सिंह के जिस शासन को बिहार का स्वर्णयुग कहा जाता है वह किनके लिए था? भूमिहार जमींदारों के लिए ही न। बहुजन आबादी बेतरह पिस रही थी। गवर्नेंस के लिहाज से उससे ज्यादा जंगलराज बिहार के इतिहास में कभी नहीं रहा। राजनीतिक भागीदारी तंत्र में सवर्ण बहुलता जिस किसी कसौटी पर कसें वह बिहार की बहुजन आबादी के लिए सबसे अंधकारमय काल था। बल्कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि लालू शासन के 15 साल और श्रीकृष्ण सिंह शासन के 15 सालों का तुलनात्मक अध्ययन हो ताकि 'जंगलराज का जो मिथ लालू शासन पर मढ़ा जाता रहा है उसकी हकीकत सामने आए? सच तो यह है कि बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार कांग्रेस शासन से ही था। कांग्रेस के चार मंत्रियों के घोटाले में संलिप्तता के कारण ही अय्यर कमेटी बनी थी जिसके कारण कई सरकारें असमय धराशाई हुईं। सच तो यह है कि श्रीकृष्ण सिंह के लंबे जंगलराज के बाद लंबे अरसे तक अस्थायी सरकारों के कारण बिहार अरसे से तबाही और यथास्थितिवाद का शिकार रहा है। यह कभी भी विकास के मैप पर रहा ही नहीं। यह मंडल के पहले शासनकाल को बदनाम करने के लिए सवर्ण पत्रकारों, अकादमिशयनों व बुद्धिजीवियों द्वारा गढ़ा गया मिथ है। जिसे बिहार के द्विज लेखकों ने और पुख्ता किया है। एक भगवाधारी नौकरशाह भगवतीशरण मिश्र ने बाजाब्ता 'अथ मुख्यमंत्री कथा' नाम से एक उपन्यास ही लिख दिया जिसमें यह मिथ और कमाल का गढ़ा गया है। यह जातिवाद पुराने लेखकों में ही हो ऐसा नहीं। बल्कि नई सदी और तेज हो रही आधुनिकता में अपने को शुमार करने वाली नई पीढ़ी के लेखकों में और बेशर्म व आक्रामक रूपों में नजर आता है। राकेश रंजन कवि हैं। प्रयोगधर्मी कवि। इनका एक उपन्यास 'मल्लू मटफोड़वा नाम से प्रकाशन संस्थान से आया है। भाषा को बरतने की कमाल की मौलिक अदा है इनकी, लेकिन दृष्टिकोण वही सामंती। देखें यह प्रसंग : 'बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनने का रोब-दाब उसमें आठों याम ऐंठता रहता था जो बात-बेबात अक्सर हिंसक रूप में प्रकट होता था। किसी की मां बहन कर देना, किसी को सरेआम मार-मार कर 'फ्लैट कर देना उसके लिए आम बात थी। किसी की जुर्रत नहीं थी कि उसका प्रतिकार करे, उसे मना करे। गालियां बकने में वह प्रयोगवादी था और मार कुटाई में परंपरावादी। परंपरावादी इस मायने में कि जूते और लाठी-फट्टे उसके पसंदीदा हथियार थे। चूंकि मोहल्ले में यादवों की संख्या सबसे अधिक थी और इस कारण वे दबंग थे और जाहिर है कि वार्ड आयुक्त भी हर बार उन्हीं में से कोई न कोई चुना जाता था, इसलिए हरि राय को किसी से डरने की जरूरत नहीं थी, दबंगई और नंगई का वह सक्रिय और निर्विरोध प्रदर्शक था।'

एक और नए लेखक हरेप्रकाश उपाध्याय की 'बखेड़ापुर' नाम से एक उपन्यासिका छपी है। यह लेखक मंडल के बारे में अपनी राय इस तरह रखता है : 'वैसे यह ठीक वही समय था जब प्रदेश की कमान एक ऐसे बेबाक और सर्वहारा किस्म के नेता के हाथ में आ गई थी, जो जेपी मूवमेंट से निकला था। जिसने प्रदेश की जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए थे, लोगों से उनकी भदेस जुबान में ही बातें करना और उन्हें ठेठ सर्वहारा अंदाज में संबोधित करना उनकी खास अदा थी। मगर प्रदेश में शासन की बागडोर संभालते ही उसने अपने तमाम लंपट और खूंखार गुर्गों को भरपूर मनमानी करने की अनौपचारिक छूट दे दी थी। चोरी और अपहरण का कारोबार काफी तेजी से फैलने लगा था। प्रशासनिक अधिकारी चूं-चपड़ करने पर सरेआम मार खाने लगे थे। पूरे राज्य में नेताओं के अलावा सभी लोग दहशत में जीने लगे थे। प्रदेश से व्यापारी और उद्योगपति पलायन कर रहे थे। ....दबंगई को वैधता मिल गई थी। .. .बड़ी संख्या में अपराधी विधायक बन गए थे। मुख्यमंत्री मंच पर आला अधिकारियों से खैनी बनवाता था। प्रदेश में ऐसे साहित्यकारों की एक जमात उभर आई थी, जो मुख्यमंत्री की तारीफ में किताबें, आरती या चालीसा आदि लिख रहे थे। ऐसी किताबों को धीरे-धीरे पाठ्यक्रमों में घुसाया जा रहा था।'

लालू का खौफ द्विज जमात के लेखक-बौद्धिकों में इस कदर व्याप्त रहा है कि बिहार की सत्ता से पिछले दस सालों से बेदखल होने के बाद भी नए परिप्रेक्ष्य और परिस्थितियों के लिए जवाबदेह वे लालू को ही मानते हैं। उक्त उद्धरण इसका सबसे ज्वलंत प्रमाण इस अर्थ में है कि लेखक ने खासतौर से शिक्षा व्यवस्था की रसातल में जा रही स्थिति को इसका आधार बनाया है। 2013 में वह इस सवाल को दर्ज कर रहा है और इसके लिए जवाबदेह 90 के लालू प्रसाद को दिखला रहा है। उक्त प्रसंग को पढ़ें तो जो सवाल पैदा होता है वह यह कि क्या किसी लेखक को सीधे-सीधे अपनी ओर से इस तरह के आरोपनुमा वक्तव्य देना चाहिए? क्या यह बेहतर नहीं होता कि इसके लिए इस तरह की कथा

शेष पृष्ठ 3 पर...

पृष्ठ 2 का शेष ...

बिहार में सृजनात्मक गद्य लेखन की विडंबनाएं

स्थितियां बनाई जातीं और पात्र ये बातें कहते ? फिर पिछले 10 सालों के इस पूरे परिप्रेक्ष्य का आज की शिक्षा व्यवस्था से क्या रिश्ता रहा है यह लेखक को रिलेट नहीं करता। सीधे-सीधे एक आम सवर्ण मंडल के बारे में जो राय रखता है वही इस लेखक का भी है। इस छोटे से उद्धरण में लेखक ने तीन अहम सवाल उठाए हैं। पहला यह कि चोरी और अपहरण कारोबार का रूप ले चुके हैं, इसी का विस्तार वह बड़ी संख्या में अपराधियों के विधायक बनने और बिहार से उद्योगपतियों के पलायन को मानता है। दूसरा प्रशासनिक अधिकारियों की नकेल कसे जाने को और तीसरा लेखकों की एक जमात जो मुख्यमंत्री की जीवनी लिख उसे पाठ्यक्रमों में शामिल करवा रहे हैं उसको।

2013 में यह सवाल 15 साल पहले के लालू शासन पर ही क्यों ? वर्तमान शासन से क्यों नहीं ? जितने सवाल लालू के संदर्भ में दर्ज किए गए हैं क्या वर्तमान शासन उससे अलग है ? क्या इस शासन में दागी विधायक नहीं हैं ? ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार और शिक्षा में मीड-डे-मिल से लेकर कांट्रेक्ट सिस्टम के लिए भी लालू ही जवाबदेह हैं ? उनके समय में शिक्षा का ऐसा बंटाधार तो नहीं हुआ फिर यह भी उनके ही मत्थे क्यों ? यह पूरा देश जानता है कि ब्रहमेश्वर मुखिया जैसा आदमी जो दर्जनों हत्याओं का आरोपी रहा है और उस हत्यारे की हत्या के बाद किस तरह बिहार में खुलेआम गुंडई का तांडव मचा और ऐसे मुजरिम को सरकार में शामिल मंत्री तक ने गांधीवादी का तमगा दिया लेकिन इस तरह की घटनाओं को उपन्यास में दर्ज करना इस लेखक को जरूरी नहीं लगा क्योंकि यह उसका जातीय मामला था। लालू के बाद के नेतृत्व में 30 कैबिनेट मंत्रियों में 14 पर आपराधिक मुकदमे के आरोप भी क्या झूठे थे ? जनता दल यूनाइटेड के 114 में से 58 विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले और 43 पर गंभीर आरोप क्या थे ? भाजपा के 90 विधायकों में 29 दागी होने की बात क्या झूठे रहे हैं ? इन सबकी अनदेखी कर कोई वर्तमान में भी अतीत के मंडल को ही आरोपी सिद्ध करता है तो यह अकारण नहीं बल्कि इसकी जड़ें रुढ़ हो चुकीं बिहार की जाति व्यवस्था में जाती हैं। इस लेखक से सवाल किया जाना चाहिए कि लालू शासन के बाद कहां बिहार में उद्योग-धंधों का जंजाल लग गया और यह भी कि क्यों और किस कारण बड़े-बड़े नामधारी बिहार विकास और विकास पुरुष की थिगलियां जोड़ बिहार को रसातल में भेजते रहे ?

इस काल का बिहार की राजनीति में सबसे अहम योगदान जिन वजहों से लालू का रहा वह पिछड़ों में सशक्तिकरण की उनकी कोशिशों के नाम रहा। जब उन्होंने जाति व्यवस्था और मीडिया के परंपरागत जातीय गठजोड़ पर चोट किया। इसे न तो 'जंगलराज' और 'कबिलाई सत्ता' जैसी सतही स्थापनाओं से समझा जा सकता है और न ही इन तथाकथित द्विजधारी लेखकों की जातीय अवधारणा में कैद होकर। इसके लिए उदार और व्यापक मानवीय दृष्टिकोण चाहिए जो इन आत्मग्रस्त लेखकों के पास नहीं है।

(अरुण नारायण युवा आलोचक हैं)

(साभार :-फारवर्ड प्रेस की बहुजन साहित्य वार्षिकी, मई 2014 से)

शेष पृष्ठ 1 का...

हैदराबाद में परिसंघ द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज का सांसद बनने पर भव्य स्वागत समारोह एवं राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

उनका स्वागत किया। एक ही आवाज चारो तरफ से आने लगी कि हमारा नेता कैसा हो- डॉ. उदित राज जैसा हो, उदित राज आगे बढ़ो-हम तुम्हारे साथ हैं। इन नारों से पूरा हॉल गुंजायमान हो उठा। लोगों का अभिवादन करते हुए उदित राज मंच पर पहुंचे। मंच का संचालन कर रहे के. महेश्वर राज ने उदित राज का स्वागत किया और कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाने की घोषणा की। डॉ. उदित राज एवं परिसंघ के पदाधिकारियों द्वारा बाबा साहेब के चित्र पर फुलमाला अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अपने स्वागत समारोह एवं राष्ट्रीय सम्मेलन में आये हुए पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए डॉ. उदित राज ने अपने भाषण में परिसंघ को मजबूत करने को कहा। डॉ. उदित राज ने कहा कि परिसंघ ही पूरे देश में अकेला सामाजिक संगठन है जो हमेशा अधिकारों की लड़ाई लड़ता है और अपने संघर्ष के द्वारा 2001 में 81वां, 82वां एवं 85वां संवैधानिक संशोधन कराकर आरक्षण को बचाया। 2011 में जब इस देश में अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार एवं जनलोकपाल की आंधी चल रही थी तो उस समय परिसंघ ही एक ऐसा संगठन था जिसने इंडिया गेट पर लाखों की रैली करके अन्ना हजारे को जन लोकपाल में आरक्षण के लिए ललकारा एवं अपना बहुजन लोकपाल बिल सरकार के समक्ष पेश किया एवं उसमें दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक की भागीदारी की बात कही। जब यह सरकार द्वारा बिल पास हुआ तो उसमें इन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला। यह केवल परिसंघ की ही देन है। इसलिए परिसंघ को हमें पहले से 10 गुणा ज्यादा मजबूत बनाना है एवं सड़कों पर उतरकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करना है ताकि जो हमारी मुख्य मांगे हैं जैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, आरक्षण कानून एवं उच्च न्यायपालिका में आरक्षण आदि को प्राप्त कर सकें। सफाई के पेशे एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कराना है।

उदित राज ने आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए लोकसभा में चुनकर नहीं गया हूं। दलित एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए संसद में आवाज उठाने एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आया हूं और दलित समाज के लिए मैं वर्षों से कटिबद्ध रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सरकार के संज्ञान में निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण एवं दलित एवं कमजोर वर्गों के अधिकार हैं जिसे मोदी सरकार से हम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। यदि परिसंघ दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर उतरकर लड़ता है तो निश्चित रूप से हम अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए कामयाब होंगे। प्रथम सत्र में के. महेश्वर राज, जे. बी. राजू एवं आंध्र प्रदेश के परिसंघ के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखें एवं परिसंघ को प्रदेश में मजबूत बनाने का संकल्प लिया एवं देशभर में परिसंघ को मजबूत बनाने के लिए अपील की।

दूसरे सत्र में जोसफ डिसूजा (ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल), के. माधव राव (सेवानिवृत मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार), विनोद कुमार (राष्ट्रीय महासचिव, परिसंघ), जगजीवन प्रसाद (राष्ट्रीय संयोजक), परमहंस प्रसाद (मध्यप्रदेश), महा सिंह भूरानिया (हरियाणा), सत्य प्रकाश जरावता (हरियाणा), सपन हल्दर, रामेश्वर राम, बी. बी. मंडल, ई. बी. राजू (पश्चिम बंगाल), सिद्धार्थ भोजने, पाटिल, हर्षवर्धन दवणे (महाराष्ट्र), ब्रहम प्रकाश, डॉ. नाहर सिंह, रमेश जाटव, एन. डी. राम, जगत सिंह ठंक, करम सिंह, संजय राज, सत्य नारायण, डॉ. काजल, रमेश कुमार, वी. पी. सिंह और दयाराम (दिल्ली), श्री निवासुलू, सतीश बोगड़ा, श्रीधरन (कर्नाटक), के. रमनकुट्टी (केरल), अनिल मेश्राम (छत्तीसगढ़), सी. टी. सिवान (तमिलनाडु), धीरेंद्र कुमार (बिहार), भारती (उत्तराखंड), डी. के. सिंह (उत्तर प्रदेश) ने दलित उत्थान एवं परिसंघ को मजबूत रखने संबंधी अपने-अपने विचार रखें। इसके तुरंत बाद परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद डॉ. उदित राज को के. महेश्वर राज एवं उनके सहयोगियों द्वारा फुलमाला एवं गुलदस्ते दिए जाने की मंच के माध्यम से घोषणा हुई। उदित राज को माला एवं गुलदस्ते देने वालों का तांता लग गया जिसे बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया गया। अंत में के. महेश्वर राज एवं सहयोगियों द्वारा डॉ. उदित राज को बाबा साहेब का बड़ा मोमेंटो देकर एवं बड़ी फुलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद डॉ. उदित राज, विनोद कुमार एवं के. महेश्वर राज ने परिसंघ के समस्त देश से आये पदाधिकारियों को बाबा साहेब का मोमेंटो देकर सम्मानित और राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया।

दूसरे दिन 7 जुलाई, 2014 को परिसंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अंबेडकर भवन, ओल्ड मिंट कंपाउंड, हैदराबाद में शुरू हुई जिसकी अध्यक्षता डॉ. उदित राज ने किया। जिसमें मुख्य रूप से परिसंघ को मजबूत करने एवं राष्ट्रीय सेमिनार अगस्त महीने में दिल्ली में आयोजित कराने पर चर्चा की।

Rest of Page 7...

NATIONAL SEMINAR HELD ON 6.7.2014 AT HYDERABAD

Society. BSP has gone down all over the country and the Dalit Movement is sinking. Without Dalit Movement,the government will hear our voices. K.Chandra Shekar Rao cheated Daliths and he became the Chief Minister and all the important Port-folios to his Family Members. Unfortunately the force behind him or Telangana Movement is SC/ST/OBC people. He urged the audience to help NSOSYF and said that helping NSOSYF is helping future generations.

Shri Kaki Madhava Rao, IAS (Retd) presided the National Seminar and assured every support to AICSTSCO in all struggles and programmes.

Shri Joseph D'Souza, National Chairman, All India Christian Council said that Dr. Udit Raj has changed our lives and we started 100 Schools in India. Nearly 30,000 students belonging to SC/ST/OBC are studying in English medium Schools and are being given a chance to become well-rounded individuals. Now their aim is to set up 1000 such schools. Given the rapid advancements in techonology, it is the need of the hour that our people are empowered with IT knowledge. The future belongs to technologically-aware people. We should fight for Reservation in Private Sector and at the same time we remain abreast with Technology. Economic Empowerment is very much required. We should also think as to how we can bring Economic Empowerment to our people. After May 16th Election Results, Mr. Ambani's shares increased by 8% which means 5000 Crores increase. Modi spent 700 Crores, Obama 100 Crores in their respective elections. With adequate financial resources only, we can get Political space. We must empower ourselves with education and technology.

Dr. Gali Vinod, Principal, Law College had said that Reservation is a Brahmanical Conspiracy. Dr. Ambedkar proved that we are inferior to anybody. KR Narayanan name was recommended for President due to the resultant efforts of Dr. Ambedkar and Shri Kanshi Ram ji ,not because of Mayawathi Ji. There are 32 High Court Judges and among them 18 Brahmins, 6 Reddy, 6 Kamma, 4 Kapu, 4 OBC, 2 SC and No Women. The upper-castes dominate the Higher Judiciary. This is undemocratic. Every Department should have Democracy. Reservation is our Fundamental Right. When there is Reservation in IAS/IPS why not in Higher Judiciary?

MEETING OF CONFEDERATION LEADERS ON 7.7.2014 AT AMBEDKAR SPHOORTHY BHAVAN

After thorough discussion for strengthening Confederation all over India, Mementos and Delegate Bags / Kits were presented to all Delegates by Dr. Udit Raj.

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशि:

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

UPSC द्वारा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के साथ किया जा रहा है अन्याय

मूलचंद्र सिंह

वर्ष 2011 से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा में भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा में परिवर्तन किया गया। इस परिवर्तन में सभी उम्मीदवारों के लिए 22 से 25 अंकों का अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अनिवार्य परीक्षण कर दिया गया।

प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य करने से भारतीय भाषाओं के माध्यम से मुख्य परीक्षा देने वालों की संख्या 4196 थी। यह 2011 में घटकर 1700 हो गई।

यह सर्वविदित है कि भारत में किसी भी वर्ग की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। गणराज्य और लोकतंत्र में प्रशासन की भाषा जनता की भाषा होनी चाहिए इसलिए जो सिविल सेवा में चयन किये जाते हैं उन्हें अपर काडर के राज्य की भाषा सीखना आवश्यक होता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी यह स्वीकार किया कि भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों की वास्तविक व्यथा है और भारत सरकार तथा लोक सेवा आयोग को यह निर्देश दिया कि इस पर सम्य विचार किया जाये।

भारतीय भाषाओं के साथ विभेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकारिया आयोग ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा था कि

Proficieny in a particular language need not be insisted upon at the time of recruitment or subsequent career in service. A person selected for a job usually acquires requisite knowledge of the language in the course of his work. In this he can be assisted by in service training.

The work of the government both union and the states which involves or affects local people must be carried on in local language. This is even more important in a welfare state. It is necessary that all forms, applications, letters, bills, notices etc. are available in the local language as well as official language.

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री अरूण निगवेकर की अध्यक्षता में सिविल सेवा परीक्षा के पुनरीक्षण के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन में यह कहा कि

1) ''सी सैट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है।''

2) ''वे प्रतियोगी जिनकी सामान्य अध्ययन पर पकड़ नहीं है, वे भी सफल हो रहे हैं जिसकी मुख्य वजह सी मैट पर अच्छी पकड़ होना है जबकि सामान्य अध्ययन में कठिनाई का स्तर ऊंचा होने के कारण इसमें अच्छी पकड़ होने पर भी प्रतियोगी के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन हो जाता है।''

यह स्पष्ट कर दे कि भारतीय भाषा माध्यम वाले परीक्षार्थी कोई रियायत या पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं चाहते हैं। वे केवल यह चाहते हैं कि परीक्षा की संरचना ऐसी हो कि सबको समान अवसर प्राप्त हो जिसकी घोषणा संविधान की उद्देशिका में की गई है।

सरकारिया आयोग, निगवेकर समिति और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश से हमारे विचार का पक्षपोषण होता है। अतएव विनम्र निवेदन है कि भारतीय भाषाओं के प्रति विद्वेषपूर्ण व्यवहार को समाप्त करे और भारतीय भाषाओं के माध्यम के परीक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करें।

हम सभी लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी हैं और भारतीय भाषा (जैसे हिंदी, गुजराती, कन्नड़, मराठी या बांग्ला) के माध्यम से इस कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हममें से अधिकांश उम्मीदवार ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि यूपीएससी वर्ष 2011 से लगातार भारतीय भाषाओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियां लागू कर रही है।

इस संदर्भ में हमारी निम्नलिखित मांगे हैं : –

1. प्रारंभिक परीक्षा में सी-मैट (पेपर 2) को हटाया जाए क्योंकि यह हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं, ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को अनुचित नुकसान पहुंचाता है। सी मैट पेपर को हटाने के संबंध में निम्नलिखित विकल्प हो सकते हैं :-

क) प्रारंभिक परीक्षा में एक ही पेपर रखा जाए जो सामान्य अध्ययन का हो। इसी में अभिवृत्ति (Aptitude) से संबंधित कुछ प्रश्न शामिल हों जो कि भाषा पर आधारित न हों।

ख) वर्तमान पद्धति के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर ही रहें पर सी मैट या पेपर 2 को सिर्फ क्वालिफाईंग स्तर का रखा जाए, मैरिट के निर्धारण में उसके अंकों को न जोड़ा जाए।

2. प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों का हिंदी अनुवाद सही होना चाहिए।

3. साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों को स्पष्ट निर्देश दिये जाएं कि वे हिंदी या अन्य किसी भारतीय भाषा के माध्यम वाले उम्मीदवार को अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य न करें।

कुछ स्पष्टीकरण व तथ्य

मांगों के संबंध में यहां कुछ स्पष्टीकरण, तथ्य व तर्क दिये गए हैं। कृपया उन्हें क्रमवार देखने से पहले निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देने का कष्ट करें :-

1. सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम में भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों का अनुपात 2005-2010 के दौरान जहां 15-20 प्रतिशत के बीच रहता था, वह 2013 में घटकर सिर्फ 4.7 प्रतिशत के आसपास रह गया है। इस वर्ष कुल 1122 सफल उम्मीदवारों में से लगभग 53 ही भारतीय भाषाओं से है। जिसमें हिंदी माध्यम को विशेष हानि हुई है तथा इनका अनुपात 10-15 प्रतिशत से 2.3 प्रतिशत हो गया है।

2. जहां पिछले कई वर्षों में हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों ने पहले 10 रैंक के भीतर (जैसे तीसरा, पांचवा, छठा रैंक) पहुंचकर दिखाया है, वहां 2013 में पहले 100 स्थानों में इसका एक भी उम्मीदवार नहीं पहुंच सका है।

3. प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों की सफलता दर 2008-2010 के दौरान जहां 40-45 प्रतिशत के बीच रहती थी, वह 2011 में सी सैट की परीक्षा लागू होते ही लगभग 15 प्रतिशत रह गई है।

अब विभिन्न मांगों के स्पष्टीकरण :-

मांग-1 का स्पष्टीकरण : ध्यान आकर्षित करने वाली बात यह है कि जहां 2008-2010 के दौरान सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों की संख्या प्रायः 35 से 45 प्रतिशत के बीच रहती थी, वह 2011 में सी सैट की परीक्षा लागू होते ही लगभग 15 प्रतिशत रह गई। तब से अभी तक यह संख्या प्रायः इसके आसपास ही है। ध्यातव्य है कि जिस अनुपात में हिंदी माध्यम के उम्मीदवार बाहर हुए हैं उसी अनुपात में अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यमों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है जबकि अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों की सफलता दर उसी अनुपात में बढ़ी है।

तालिका-1 में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2011 से भारतीय भाषाओं के उम्मीदवारों का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :-

1. सी सैट (पेपर 2) परीक्षा में 80 में से 8-9 प्रश्न सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पूछे जाते हैं, जिसके लगभग 22.5 अंक है। इससे हिंदी व अन्य भाषा माध्यमों के उम्मीदवारों को भाषायी आधार पर अवसर की समानता से वंचित किया जाता है।

2. सी सैट में लगभग 30-36 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन क्षमता पर आधारित होते हैं जिनमें मूल पाठ अंग्रेजी में होता है तथा उसका हिंदी अनुवाद त्रुटिपूर्ण होता है। यह भाषायी अनुवाद भेदभाव को परिलक्षित करता है।

स्वयं यूपीएससी द्वारा गठित निगवेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है, जैसे

1) सी सैट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है।

2) वे प्रतियोगी जिनकी सामान्य अध्ययन पर पकड़ नहीं है, वे भी सफल हो रहे हैं जिसकी मुख्य वजह सी सैट पर अच्छी पकड़ होना है जबकि सामान्य अध्ययन में कठिनाई का स्तर ऊंचा होने के कारण इसमें अच्छी पकड़ होने पर भी प्रतियोगी के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना कठिन हो जाता है।

इसलिए हमारा निवेदन है कि इस प्रश्नपत्र को हटाया जाए तथा मांग-1 के साथ दिये गए दो विकल्पों में से किसी एक पर विचार किया जाए।

मांग-2 का स्पष्टीकरण : प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नपत्र पहले अंग्रेजी में बनाए जाते हैं और फिर उनका हिंदी अनुवाद कराया जाता है। यह अनुवाद कई मामलों में त्रुटिपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए –

क) वर्ष 2013 के सामान्य अध्ययन के पेपर-3 में

1) प्रश्न 8 का अनुवाद करते हुए 'Land Reform' शब्द का अनुवाद आर्थिक सुधार किया गया।

2) प्रश्न 9 (a) का अनुवाद अधूरा है।

3) प्रश्न 9 (b) में 'Joint Venture Route' का अनुवाद 'संयुक्त संधिमार्ग' दिया गया है जिसे शायद ही कोई समझ सके।

4) प्रश्न 19 में 'Go and No Go Zone' का अनुवाद 'हां' या 'नहीं' अवधारणा दिया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है।

शेष पृष्ठ 6 पर ...

तालिका :-1

वर्ष	2008	2009	2010	2011	2012
मुख्य परीक्षा कुल अभ्यर्थी	11279	11456	11777	11097	12176
अंग्रेजी माध्यम के	5817	6244	7329	9203	9961
अंग्रेजी माध्यम (%)	51.6 %	54.5 %	62.2 %	82.9 %	81.8 %
हिंदी माध्यम के	5082	4865	4196	1700	1976
हिंदी माध्यम (%)	45.1 %	42.5 %	35.6 %	15.3 %	16.2 %
कन्नड़ माध्यम के	14	11	11	5	NA
तेलगू माध्यम के	117	85	69	29	NA
तमिल माध्यम के	98	90	38	14	NA

स्त्रोत : आरटीआई

पहले मिले अधिकार को सुरक्षित रखे बगैर शासक नहीं बना जा सकता : उदित राज

नेतराम ठ्गेला

अखिल भारतीय अम्बेडकर विचार मंच की ओर से दिनांक 29 जून 2014 को अधिकार सम्मेलन श्री मनी राम सरोही की अध्यक्षता में भगवती धर्मशाला, भिवानी (हरियाणा) में किया गया। इसका उद्घाटन स्वामी वीर सिंह, हितकारी जी महाराज (बुलन्दशहर, उ.प्रदेश) ने किया। इस अवसर पर डा. उदित राज, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के सांसद बनने पर उनका भव्य अभिनन्दन किया गया। इसके अतिरिक्त श्री आर.सी. चौहान, आई.आर.ए.एस. (सेवानिवृत), श्री नेतराम ठ्गेला, रा. महासचिव परिसंघ, श्री महा सिंह भुरानिया, अध्यक्ष, श्री राजेन्द्र जोगपाल, महासचिव हरियाणा प्रदेश परिसंघ, श्री सत्यप्रकाश जरावता, अध्यक्ष लार्ड बुद्धा क्लब, हरियाणा आदि का भव्य अभिनन्दन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि डा. उदित राज, सांसद एवं अध्यक्ष परिसंघ ने कहा कि जब तक अनुसूचित समाज एक नहीं होगा अपने ऊपर हुये हजारों साल के शोषण को समाप्त नहीं कर सकता। हम बात करते है हमारी आबादी के हिसाब से हमारे न्यायाधीश, खिलाड़ी, व्यापारी, मीडिया में हो। यह सब हो सकता है मगर इसके लिये आपको अनुसूचित समाज में व्याप्त जात-पात के भेदभाव को छोड़ना पड़ेगा। परिसंघ मानसिक संतुष्टि की लड़ाई नहीं लड़ता बल्कि परिणाम पाने के लिए लड़ता है। परिसंघ आरक्षण को बचाने के लिये बना। हमने आन्दोलन चलाकर उसे काफी हद तक बचाया है। अब हम निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए लड़ रहे है, हमने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जिसके परिणामस्वरूप डा. मनमोहन सिंह ने इसके लिये तीन कमेटियां बनाई मगर परिणाम शून्य आया। एन.डी.ए. सरकार ने तीन आरक्षण विरोधी आदेश वापिस करवाये थे, उस पृष्ठभूमि को देखते हुये अपनी मांगे सरकार से पूरी करवाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। इससे पूर्व ढाई वर्ष हमने मायावती को भी ठ्टोला मगर वहां मुद्दों की बात तो होती ही नहीं हैं। वे कहते है हम याचक नही शासक बनेंगे। अच्छी बात है बनना ही चाहिये। मगर प्रत्येक समाज की एक ताकत होती है। वैश्य समाज की ताकत व्यवसाय है, जाट-गुर्जर की ताकत जमीन है, ब्राह्मण की शिक्षा और धर्म है। उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से अनुसूचित समाज की ताकत हम कर्मचारी अधिकारी ही हैं। 1991 में आर्थिक उदारवाद और दलित आन्दोलन एक साथ चरम सीमा पर था। उस समय हम तो मैदान में थे ही नहीं। शासक बनने की सोच अच्छी है मगर जो आपके पास अधिकारी और कर्मचारी की ताकत है उसे तो पहले बचाते। निजीकरण या तो रोकते अथवा उसमें भागीदारी के लिए आन्दोलन चलाते। अपना सब कुछ गंवा कर शासक नहीं बना जाता।

डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहा कि यदि आप भारत को विकसित, सुद्ढ बनाना चाहते है तो उसका रास्ता अनुसूचित समाज की ओर से होकर जाता है। उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। भाजपा ने इसमें सहमति व्यक्त की। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जानते थे कि उनकी ताकत पूरी दुनिया में है मगर एक क्षेत्र में जीतने के लिये कांग्रेस की मदद चाहिये। वे कांग्रेस की मदद से बने, हमने भी बहुत प्रयास किया। हम चुनाव भी लड़े लेकिन क्या मिला? हमारी ताकत पूरे भारत में लाखों लोगों को लामबन्द करने की है मगर चुनाव तो एक क्षेत्र से जीता जाता है। वहां हम कमजोर है इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले। पार्टी ने हमे सांसद बनाया और हमारे कारण

वे कई सारी सीट जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने आगे कहा चाहे आज सांसद हूं मगर मेरा पहला प्यार परिसंघ है। परिसंघ को मजबूत बनाने से हमारी समस्याओं का समाधान होगा।

श्री नेतराम ठ्गेला, रा. महासचिव परिसंघ, अध्यक्ष ए.एफ.एच.कयु. सिविलियन (ग्रुप ए) आफिसर एसोसिएशन (भारत सरकार से मान्यता प्राप्त) ने याद दिलाया कि 1997 में आरक्षण विरोधी आदेशों को वापिस कराने के लिये डा. उदित राज के नेतृत्व में परिसंघ बना, उनके गतिशील नेतृत्व के कारण यह केवल दिल्ली का आन्दोलन नहीं वरन् चण्डीगढ, लखनऊ, चेन्नई, बैंग्लुरु, आदि से होता हुआ देश के हर कस्बे, हर जिले, हर तहसील में हजारों लोग घर से बाहर निकले। इस आरक्षण को बचाने की मुहिम में 2000 में दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली से पूरा भारत अचंभित रह गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि चार में से तीन आरक्षण विरोधी संविधान में संशोधन करके वापिस हुये।

इसके बाद परिसंघ ने डा. उदित राज के नेतृत्व में निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाई, उन्होंने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि अभी निजी क्षेत्र में आरक्षण का काम अधूरा पड़ा है, आरक्षण कानून और पदोन्नति में आरक्षण के अलावा अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों को मान्यता दिलाने के लिए आज हमारे पास डा. उदित राज के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक ऐसा शख्स सांसद के रूप में चुनकर आया है जिसका एक विजन है, मिशन है जिसमें साहस है। मगर उपरोक्त मुद्दे इतने व्यापक है कि डा. उदित राज अकेले यह काम नहीं कर सकते इसके लिए हर गांव, तहसील, कस्बे, जिले व प्रदेश के लोगों को घरों से उसी प्रकार से निकल कर आना होगा जैसे 2000 की रैली में आये थे। परिसंघ उदित राज के नेतृत्व में आपकी आवाज बुलन्द करेंगे और अन्दर सांसद के तौर पर डॉ. उदित राज आपकी मांगे पूरी करवायेंगे।

श्री महासिंह भुरानिया, अध्यक्ष ने कहा कि डा. उदित राज के नेतृत्व मे हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। जिस प्रकार से उन्होंने केन्द्र में अधिकार दिलवाये उसी प्रकार से हरियाणावासियों को आन्दोलन से अपने अधिकार लेने होंगे। श्री राजेन्द्र जोगपाल, महासचिव हरियाणा परिसंघ (सुपरिटेन्डेंट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन) ने मांग-पत्र पढ्ते हुये पदोन्नति व निजी क्षेत्र के आरक्षण पर बल दिया। श्री सत्य प्रकाश जरावता, अध्यक्ष हरियाणा बुद्धा कलब ने कहा कि आज हरियाणा जाग गया है। कल हमने गुड़गाव में विशाल कार्यक्रम किया, आज यहां हो रहा है। श्री आर. सी. चौहान, आई. आर.ए.एस. (सेवानिवृत) ने डा. उदित राज के नेतृत्व में समाज परिवर्तन के काम में सबसे सहयोग देने का आग्रह किया। श्री जरावता ने आगे कहा कि डॉ. उदित राज के कारण देश के दलित भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं लेकिन हरियाणा में आगामी मुख्यमंत्री या तो दलित होगा या दलित समाज जिसे चाहेगा वह होगा। हरियाणा के दलित डॉ. उदित राज के एक इशारे पर किसी की भी सरकार को बनवा सकती है। अध्यक्षता करते हुये श्री मनी राम सरोही ने परिसंघ के विगत समय के आन्दोलन में हरियाणा के दिये योगदान के बारे मे बताते हुये कहा कि एक बार फिर हरियाणा उसी दिशा में कार्य करेगा। इस अवसर पर श्री चन्द्र मोहन, प्रधान हरियाणा प्रदेश अनुसूचित जाति अध्यापक संघ, श्री विजय सरोही, प्रधान श्री रविदास सभा, भिवानी, श्री अनिल कुमार, श्री कर्मा सिह, श्री अरविन्द कुमार, ड्रा. एल.एल. बुन्देला, श्री अशोक ठ्गेला आदि ने अपने-अपने विचार रखे।

उदित राज सहित तीन नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान

संजय अधांगले

गत् दिनों 5 जुलाई, 2014 को मुंबई के वसंत स्मृति, भाजपा कार्यालय, तृतीय तल, दादा साहेब फाल्के रोड, दादर (पूर्व) में अनुसूचित जाति के तीन नवनिर्वाचित सांसदों डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिमी दिल्ली), डॉ. सुनील गायकवाड (लातूर) एवं एडवोकेट शरद बनसोडे (सोलापूर) का स्वागत किया गया। यह स्वागत समारोह अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा मुंबई एवं अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से किया गया।

इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय सामाजिक समरसता मंच के संयोजक माननीय दादा इदाते, माजी राज्यमंत्री विजय (भाई) गिरकर, अनुसूचित जाति मोर्चा, भाजपा, मुंबई के अध्यक्ष शरद कांबले, भाजपा, मुंबई के उपाध्यक्ष रमेश मेढेकर और परिसंघ के सभी पदाधिकारी और विभिन्न जाति एवं संगठनों के प्रमुख लोग उपस्थित थे।

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित भाजपा सांसद डॉ. उदित राज ने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक दलितों को अपना अधिकार मिलना मुश्किल है। जाति व्यवस्था के कारण भारत सदियों से गुलाम रहा है। अनुसूचित जाति के लोगों के सक्षम बनने के बिना देश मजबूत नहीं हो सकता इसलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण होना जरूरी है। भाजपा एवं संघ को देश की जनता ने यह मौका प्रदान किया है कि अगर भाजपा को भारत में 50 साल राज करना है तो देश में सामाजिक एकता का निर्माण करना होगा। जाति व्यवस्था को यदि नष्ट करना है तो संघ को इसके लिए

ईमानदारी से काम करना होगा। भाजपा को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को बराबर की भागीदारी देनी होगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है।

डॉ. सुनील गायकवाड, एडवोकेट शदर बनसोडे सहित विजय (भाई) गिरकर ने भी अपने-अपने विचार उपस्थित लोगों के समक्ष रखा। विजय (भाई) गिरकर ने कहा कि जैसे देश कांग्रेस मुक्त हो गया है वैसे ही महाराष्ट्र को भी कांग्रेस मुक्त बनाना है।

इस कार्यक्रम का संचालन शरद कांबले ने किया।

कबीर के मामले में केजरीवाल चुप !

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सही मायने में इस समय देश के एनजीओ सरगना हैं। मेधा पाटकर हो या पी. उदयकुमार, सभी एनजीओकर्मी उनकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। एनजीओ को राजनीतिक पार्टी में बदलकर सत्ता हासिल करने का खेल खेलने वाले अरविंद केजरीवाल का विदेशी कनेक्शन पूर्व यूपीए सरकार की जांच में सामने आ चुका है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनजीओ गिरोह 'राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी)' ने घोर सांप्रदायिक 'सांप्रदायिक और लक्ष्य केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम' का ड्राफ्ट तैयार किया था। एनएसी की एक प्रमुख सदस्य अरुणा राय के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी में रहते हुए एनजीओ की कार्यप्रणाली समझी और फिर 'परिवर्तन' नामक एनजीओ से जुड़ गए। वर्ष 2006 में 'परिवर्तन' में काम करने के दौरान ही उन्हें अमरीकी 'फोर्ड फाउंडेशन' व 'राकफेलर ब्रदर्स फंड' ने उभरते नेतृत्व के लिए 'रेमन मैगसायसाय' पुरस्कार दिया, जबकि उस वक्त तक अरविंद ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया था, जिसे उभरते हुए नेतृत्व का प्रतीक माना जा सके! इसके बाद अरविंद ने उस धन से 19 दिसंबर 2006 को पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन (पीसीआरएफ) नामक संस्था का गठन किया और अपने पुराने सहयोगी मनीष सिसोदिया के एनजीओ 'कबीर' से जुड़े। 'कबीर' का गठन इन दोनों ने वर्ष 2005 में किया था।

गृहमंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एनजीओ कबीर का औपचारिक पंजीकरण अगस्त 2005 में हुआ, लेकिन फोर्ड ने उसे जुलाई 2005 में ही फंड उपलब्ध करा दिया, जबकि कानूनन किसी एनजीओ को लंबे समय तक काम करने के उपरांत ही विदेशी चंदा मिल सकता है। यह अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया के पूरे एनजीओ गिरोह के अमरीकी कनेक्शन को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा सबूत है। 'फोर्ड फाउंडेशन' के अधिकारी स्टीवन सलनिक ने भी एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में माना कि 'कबीर को फोर्ड फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2005 में 1 लाख 72 हजार डालर एवं वर्ष 2008 में 1 लाख 97 हजार अमरीकी डालर का चंदा दिया गया।' यही नहीं, 'कबीर' को 'डच दूतावास' से भी मोटी रकम चंदे के रूप में मिली है। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के एनजीओ कबीर को अमरीका से एवं उनके एक अन्य एनजीओ परिवर्तन को नीदरलैंड की एनजीओ 'हिवोस' से जबरदस्त फंडिंग हुई है। हिवोस ने भारतीय एनजीओ को अप्रैल 2008 से 2012 के बीच लगभग 13 लाख यूरो, मतलब करीब सवा नौ करोड़ रुपए की फंडिंग की है। मजे की बात देखिए कि 'हिवोस' को भी अमरीकी फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग करती है। डच एनजीओ 'हिवोस' दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केवल उन्हीं एनजीओ को चंदा देती है, जो अपने देश व वहां के राज्यों में अमरीका व यूरोप के हित में काम करते हैं।

केवल चार साल में विदेशों से आ चुकी है 40 हजार करोड़ की रकम

ग्रीनपीस, मेधा पाटकर, पी. उदयकुमार, तीस्ता सीतलवाड़, अरविंद केजरीवाल एंड गिरोह तो कुछ नाम भर हैं। पूर्व गृहराज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2005-2009 के दौरान देश में 77 हजार 850 एनजीओ को विदेशों से 40 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। उनके अनुसार, 2005-06 में 18,650 एनजीओ को 7889.12 करोड़ रुपए मिले थे। इसके बाद 2006-07 में 19,462 एनजीओ को 11,111.12 करोड़ रुपए, 2007-08 में 19,247 एनजीओ को 9723.96 करोड़ रुपए और 2008-09 में 20,499 एनजीओ को 10,837.49 करोड़ रुपए के बराबर सहायता राशि या चंदा विदेश से मिला।

(साभार : पांचजन्य)

शेष पृष्ठ 4 का ...

UPSC द्वारा हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों के साथ किया जा रहा है अन्याय

ख) 2013 के समान्य अध्ययन के पेपर-4 के प्रश्न 14 में 'Star Performer' का अनुवाद 'नायककर्ता' किया गया है।

ध्यातव्य है कि स्वयं यूपीएससी द्वारा गठित निगवेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि अंग्रेजी से किया जाने वाला अनुवाद मशीनी किस्म का होता है।

इस समस्या के संबंध में हमारा निवेदन है कि सर्वप्रथम ऐसे अनुवाद की व्यवस्था कराई जाए जो अंग्रेजी प्रश्नों के एकदम बराबर या समतुल्य हो। दूसरे, किसी स्वतंत्र अनुवाद संस्था से प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के प्रश्नपत्रों का परीक्षण कराके यह सुनिश्चित किया जाए कि गैर अंग्रेजीभाषी उम्मीदवारों को जितने अंकों का संभावित नुकसान हुआ है, उतने अंक उनके प्राप्तांकों में जोड़े जाएं।

मांग-3 का स्पष्टीकरण : हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रतियोगी जब साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो कई बार उनसे अंग्रेजी में सवाल पूछे जाते हैं और स्पष्ट/परोक्ष दबाव बनाया जाता है कि वे अंग्रेजी में ही जवाब दें।

यदि आप किसी वर्ष साक्षात्कार में अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों को औसतन 55-65 प्रतिशत अंक दिये जाते हैं, वहीं हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को 40-45 प्रतिशत मात्र। यह अंतर भी भाषायी भेदभाव की मानसिकता को स्पष्ट करता है।

निम्नलिखित तालिक-2 को ध्यान से देखें :-

	वर्ष	2003	2004	2005	2009	2010	2011	2012	2013
मुख्य परीक्षा	कुल अभ्यर्थी	5750	5328	4926	11456	11777	11097	12176	14959
	हिंदी माध्यम के	2469	2192	1880	4865	4196	1700	1976	------
	हिंदी माध्यम का(%)	42.9 %	41.1%	38.2 %	42.5 %	35.6 %	15.3 %	16.2 %	-------
साक्षात्कार	कुल अभ्यर्थी	1179	1163	1174	------	-----	----	----	3003
	हिंदी माध्यम के	303	244	283	730	562	301	----	----
	हिंदी माध्यम का(%)	25.7 %	21 %	24.1 %	----	----	----	----	----
अंतिम परिणाम	कुल अभ्यर्थी	457	453	425	875	920	910	998	1122
	हिंदी माध्यम के	49	53	65	222	125	89	----	26
	हिंदी माध्यम का(%)	10.7 %	11.7 %	15.3 %	25.4 %	13.9 %	9.8 %	----	2.3 %

तालिका :-2 ***स्रोत : आरटीआई***

इस तालिका को देखकर यह समझना मुश्किल नहीं है कि मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में हिंदी माध्यम के उम्मीदवार किस तरह पीछे छूटते जाते हैं। यही कारण है कि 2013 के अंतिम परिणाम में पहले 100 स्थानों में हिंदी माध्यम का एक भी उम्मीदवार नहीं है जबकि पहले यह संख्या 15-20 तक रहती आई है (जैसे 2002 तथा 2008 में)। हिंदी माध्यम के उम्मीदवार 3,5,6,7,8,9,10,13 तथा 15 जैसे ऊंचे स्थानों पर चुने जा चुके हैं।

हम जानते हैं कि आपकी सरकार भारतीय भाषाओं तथा ग्रामीण समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाती रही है। आपके मंत्रियों द्वारा हिंदी, संस्कृत व अन्य भारतीय भाषाओं में शपथ लिए जाने तथा गृह मंत्रालयों आदि में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने की कोशिशों से हमें तथा देश के अधिकांश लोगों को गहरी उम्मीद बंधी है। हमें आशा है कि आप संविधान के अनुच्छेद-343 और 351 की भावना के अनुरूप प्रशासन के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा में भी भाषायी भेदभाव को समाप्त करेंगे। हम यह नहीं चाहते कि हमें अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की तुलना में अनुचित लाभ मिले। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे साथ या अन्य भारतीय भाषाओं के साथ कोई अन्याय न हो।

जनता ने वादा खिलाफी की सजा दी कांग्रेस को :-उदित राज

गुड़गांव, 28 जून, 2014। दिल्ली से भाजपा सांसद डा. उदित राज ने कहा है कि जनता के साथ विश्वासघात की सजा कांग्रेस को मिल गई है। कांग्रेस ने हमेशा लोगों के भरोसे को तोड़ा, न तो देश में और न ही हरियाणा प्रदेश में दलित समाज से किए गए किसी भी वायदे को पूरा किया। यही वजह है कि आज कांग्रेस देश की सत्ता से बाहर हो गई और प्रदेश से भी बाहर होने जा रही है। आज डॉ. उदित राज गुड़गांव के एक होटल में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ एवं लार्ड बुद्धा क्लब गुडगांव द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। सांसद ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार दलितों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया कि दलितों को हर क्षेत्र में उचित भागीदारी मिलेगी और उनके संगठन की पुरानी मांग निजी क्षेत्र में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण आदि पूरी होंगी। हरियाणा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा एवं उसके सहयोगी दल दलितों को पार्टी एवं हर क्षेत्र में उचित भागीदारी दें ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में दलित वर्ग बढ़चढ़ कर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के साथ जा सके। कार्यक्रम के संयोजक लार्ड बुद्धा क्लब के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता ने प्रदेश सरकार पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। प्रदेश सरकार ने न तो 85 वां संविधान संशोधन लागू किया है और न ही प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति में आरक्षण दिया है।

इस मौके पर खेमचंद डावला, ओम नारायण, कंवर सिंह, साधू सिंह, जितेन्द्र कादीपुर, राजेश शास्त्री, राजेन्द्र जोगपाल, राजेन्द्र प्रसाद, सुमेर सिंह तंवर, महेश रूबी आदि मौजूद थे।

Pro Reservation Conference Organised in Jammu, Dr. Udit Raj Presides Over The One Day Conference

R. K. Kalsotra

Jammu: 13.07.2014: On the occasion of one day pro reservation conference organized by The All India Confederation of SC/ST/OBC Organizations (J&K unit) on 13th of July 2014, the core cadre of the Confederation and various social, political and religious people from all parts of the State participated and shared their immensely innovative and valuable knowledge in the conference. The conference was presided over by the National Chairman of the Confederation and Member of Parliament Dr. Udit Raj who was felicitated by the President of the State unit Mr. R. K. Kalsotra. A memorandum citing demands at the central and state level was also submitted to the Hon'ble PM of India through the Hon'ble Member of Parliament. A memorandum listing demands at the state level was also sent to the CM of the state

In today's conference, wide-ranging issues at the national and state level were discussed so that an impetus could be given upon such issues. Dr. Udit, Raj, while addressing the participants, stressed upon unity, paying back to society, spirit of sacrifice and strengthening the support system of the Confederation. Stressing on a collective effort for winning the struggle, he emphasized that a single person can only give direction but cannot bring about the change desired in a system and that SC/ST/OBC's of the nation have brought this change by contributing to the change of power at the centre.

Taking cue from the developed economies, Dr. Udit Raj stressed that on their lines the deprived sections of the society particularly SC/ST/OBC's must be allowed to participate in the private business houses by providing them reservation and then only can an era of inclusive growth usher. He further said that we cannot achieve a strong nation where there is bipolarity between people at social and economic levels. Criticizing the dual structure of the political spectrum in the J&K where the central laws have to wait for decades to be implemented, he said that a strict insulation is bound to deprive the state of good steps being taken by the government at the centre and even the west Pakistan refugees were suffering from inhuman conditions due to this particular issue and called upon the government of the state to provide citizenship rights to the west Pakistan refugees. He called upon the participants to get ready for the annual rally by the Confederation in November-December at Delhi and also for the upcoming assembly elections in the state to throw the tyrannical rule of the incumbent coalition for having deprived the SC/ST/OBC's of the state to achieve its oblique motives.

Mr. Kalsotra, while speaking on the occasion, said that he gave the slogan "Jo hamari baat karega vo Delhi me Raaj Karega" before the parliamentary elections and now on the eve of the assembly elections he is calling upon them to adhere to the same slogan for upcoming state elections too. He, however, said that the Confederation will still give a final chance to the incumbent government to accede to their demands. Moreover, he asked the people belonging to these depressed sections, particularly the youth and the students, to come together and to work for getting into the services in government as well as in private sector owing to the fact that their forefathers were poor landless labourers who had no option but to serve the higher communities. He said that few can sacrifice for the cause of the community and after Dr. Ambedkar, Dr. Udit Raj is the one. He said that inspite of applicability of article 370 in the state the state unit has many achievements to its credit like Reservation Act, One step up reservation, Inter District reservation, etc. However, the state government has consistently been working

Dr. Udit Raj addressing the Pro Reservation Conference standing next to him is R. K. Kalsotra

day and night to defeat the constitutional rights of these communities by launching surrogate litigation against people from these communities and then not defending such matters promptly which leads to deprivation of all the constitutional guarantees. Mr. Kalsotra further said that even now capital resources among these communities are lacking and the only way out to sustain is to enter into the services and that it why it becomes all the more important that we attain highest possible education to remain in the race for survival. Moreover, big business houses are at the command of higher communities who are hesitant to employ even the most intelligent candidates from these communities, as such, reservation is urgently needed in the private sector so that our progeny is not left to starve. Criticizing the statement of the vice chancellor of smvdu where he said that the reservation promotes inefficient people, he asked the government to dislodge such a man who does not believe in the constitutional schemes. Mr. Kalsotra finally called upon the government to establish Dr. Ambedkar Chair in the University of Jammu.

Others who spoke include Romesh Sarmal, Ashok Koul General Secretary BJP, Chaman Lal Kandley, Darshan Bhagat, Romesh Kaith, Babu Suman, Deepak Attri, Roshan Choudhary, Farooq Chowdhary, Mohd. Aslam Kohli, Vijay Bhagat, Mushtaq Ganai, Kumar, Ashok Bhagat, Sham Lal Basson, Girdhari Lal Lakhnotra, Sanjeev Manmotra, Madam Krishna, Harbans Kumar and others.

NATIONAL SEMINAR HELD ON 6.7.2014 AT HYDERABAD

K. Maheshwar Raj

The National Seminar of All India Confederation of SC/ST Organisations was held on 6th July, 2014 at Ravindra Bharathi Hall, Hyderabad from 10.00 AM to 8.00 PM. The Programme had three Sessions (1) State Level Convention, (2) National Level Convention and (3) National Seminar on (i) Reservation in Private Sector ; (ii) Reservation in Promotions ; (iii) Reservation in Higher Judiciary ; (iv) Reservation in Corporate Educational Institutions (v) Reservation in Dealership / Contracts ; (vi) Reservation in Commercial Complexes ; (vii) Reservation Act in Schedule-9 of the Constitution and (viii) National SC Special Component Plan and ST Sub-Plan.

Shri K.Maheshwar Raj, President of the Andhra unit had presided over the Meeting and he welcomed the Chief Guest Dr.Udit Raj, Hon'ble Member of Parliament & National Chairman of AICSCSTO, Guests of Honour, Delegates, who had come from all parts of India and Invitees & Guests. Shri K.Maheshwar Raj has told that Dalits have failed to conquer the Political Power in General Elections. Now we are not in a position to give befitting reply against the Atrocities happening all over India and the Discriminations. We are totally weakened ourselves as we are not united and are selfish. He reminded that Dr. Udit Raj is the only leader at National Level who has been relentlessly fighting for our rights and all dalits hope that he will be able to succeed in securing Reservation in Private Sector and 117th Constitutional Amendment of Reservation in Promotions apart from Reservation Act and other Demands. He requested all dalits to support Dr. Udit Raj. He concluded with an assurance of supporting Dr. Udit Raj, calling him as Black Tiger.

Dr. Udit Raj in his speech said that at present Political Movement in India is not fruitful and we need to build a Social Movement, which is very important. Joining BJP was a difficult decision which was done only after consulting the Confederation Leaders. Confederation is Strong but it is scattered all over India and we need a Nationalised Movement and not Localised Movement. SC/ST participation in Government and every Sector is required. BJP made an agreement for giving space for SC/ST in every sector. In 2004, Congress made false promises to the dalits but cheated them. BJP is comparatively better as in the past NDA Government made 82th, 84th & 85th Constitutional Amendments. The dalits and tribals have high hopes of me and I wish to serve them well. The National Seminar in the prevailing situation is very important. No party mentioning is Dr. Ambedkar & Reservations, we are totally neglected and they are winning elections. All our Organisations only criticising Brahmanism & System and not fighting for empowerment of our needy people. No Leader or any other SC/ST Organisations has contributed as much as the AICSCSTO. He said that the foremost on our agenda is Reservation in Private Sector. In 2004 GOM (Sharad Pawar etc) tried for Private Sector Reservation but it needs Constitutional Amendment. Three Committees were formed but the Bill has not been passed. Earlier Political Parties use to speak a lot for Dalit Rights, Reservations but this time no one spoke of our interests, we were neglected. It is everyone's responsibility to strengthen the Confederation. I appreciate Shri K.Maheshwar Raj, Shri JB Raju Garu for making this National Seminar a Grand Success.

Dr.Udit Raj said that his worry is how to build a Strong Political Movement? How to bring the youth in support of our cause? AP is already having Maheshwar Raj. Our meetings cant go beyong 2-3 days but RSS meetings go on for 20 days. Our Training programmes should also be at par with RSS. Swayam Sevaks don't have personal desires. Brahmins medidates in Himalayas for years and they are more committed for their

Rest on Page 3...

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 16 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 July, 2014

All India Confederation of SC/ST Organization organizes Massive Welcome Reception for the newly elected MP, Dr. Udit Raj in Hyderabad

Vinod Kumar

The welcome reception of National president of All India Confederation of SC/ST Organization, Dr. Udit Raj in Hyedrabad, on being elected as the Member of Parliament from North West Delhi was supposed to start on 6th July, 2014 at 9 am but the members of the confederation gathered a day before on 5th July itself to welcome their leader. The enthusiasm and gusto with which people had gathered reflected their joy and happiness for their leader's election to the parliament. The venue for the program saw attendance of people beginning as early as 7am on 6th of July and by the time Dr. Udit Raj arrived, the Ravindra Bharati auditorium in Hyderabad was jam packed with a crowd that was shouting slogans in favour of Dr. Raj. In his address, Dr. Udit Raj stressed on the fact that the Confederation is the only organization that has been continuously and successfully leading the fight for SC/STs. He reminded the gathering of the success of the confederation in bringing about the 81st,82nd and 85th Constitutional amendment that protected the Reservations from being clamped down. Furthermore, He said that at the time of Janlokpal Andolan led by Shri Anna Hazare, Confederation was the only organization in the country that vehemently protested for the inclusion of SC/ST reservation in the Janlokpal Draft. The result of this was that when the govt presented its own version of the Lokpal Bill, SC/STs were given adequate representation."I have not taken up the role of Member Parliament for my personal benefits; I have taken up this position for the empowerment of SC/STs and the deprived classes of the country. Protection of their rights under the Modi Government is going to be a priority for which I shall put in all my efforts", he added.

In the first session, M.K. Maheshwar Raj, J.B. Raju and the office-bearers of Andhra Pradesh Confederation spoke about their commitment to further strengthening the foundations of the organization in the state and appealed for nation-wide efforts to nationally strengthen the Confederation. The second session was attended by the various senior members of the organization and ended with the presentation of flowers and malas to the National President, Dr. Udit Raj. This was followed by a

crowd frenzy to facilitate Dr. Raj with hundreds of people lined up to present Malas to their leader. K. Maheshwar, President of the Andhra Confederation handed over a momento of Dr. B.R. Ambedkar to Dr. Raj along with Sh. Vinod Kumar.

The second day of the session saw the National executive of the Confederation meeting at Ambedkar Bhawan,Old Mint Compound, Hyedrabad under the Chairmanship of Dr. Udit Raj. The National Executive primarily discussed the ways of strengthening the Confederation all over the country and deliberated over the organization of National seminar in Delhi in the month of August.

SC/ST DEPRIVED OF THEIR SHARE IN BUDGET

The general budget was presented by Arun jaitley on 10th July and as far as SC/ST welfare is concerned, there is no change. Special Component Plan (SCSP) was initiated about 35 years ago became necessary as it was increasingly becoming clear that Scheduled Castes were not getting an adequate share of government funds. The aim of SCSP is to ensure that adequate allocations are made and spent for real needs and priorities of Dalits.

The SCSP mandates the setting apart of a proportion of the total Plan outlays of the Centre and state governments that is equivalent to the population proportion of SCs at the national and state level, for their development. Census 2011 has pegged the Scheduled Castes population at 16.6 % of the total population. In the vote-on-account budget presented in March 2014, according to rules, 16.6% of the total funds for Dalits should have been allocated, but instead, they were allocated just 8.76%. The total budget was Rs 17,63,214 crores. Under the SCSP, what was supposed to have been allocated is Rs 92,183.45 crores. But what actually was allocated is only Rs 48,638.31 crores, which is only half of what should have been allocated. Both dalits and adivasis expected to rectify this anomaly by the new government. But they have been disappointed. The actual allocation in this budget is Rs. 50,548 crores and Rs. 32,387 crores for SCs and STs respectively. The total plan allocation also declined in real terms roughly by 4%. Moreover the share of SCs and STs in total plan expenditure is falling short by Rs. 47,000 crores and Rs. 14,000 crores according to Planning Commission guidelines based on proportion of population.

Experience shows that even what is being allocated is not spent for the welfare of the Dalits. In the last year's budget (2013-14) Rs 41,561.13 crores was allocated for the SCSP, but according to the revised estimates, only Rs 35,800.6 have been spent.

There also have been several glaring cases of diversion of SCSP funds for entirely different uses such as construction of flyovers, Commonwealth Games etc.It is clear that the SCSP has been widely violated in actual practice. The 12th Plan document stated frankly, "despite the fact that strategies of TSP and SCSP had been in operation for more than three decades, they could not be implemented as effectively as desired. The expenditure in many of the states/UTs was not even 50 per cent of the allocated funds. No proper budget heads/sub heads were created to prevent diversion of funds. There was no controlling and monitoring mechanism and the planning and supervision was not as effective as it should be."

There is a great need for a well-designed, dedicated institutional setup at the Central and state level, which shall allocate SCSP funds to the ministries/departments, taking into consideration the developmental needs of SCs. This should enable the ministries/departments to clearly show the schemes formulated for the development of SCs under a separate budget head.

In this background, in order to ensure an effective implementation of the SCSP, there is an urgent need to enact a national level legislation to provide statutory backing to the provisions of the SCSP. Due to the consistent struggles , such a legislation was enacted by the Andhra Pradesh Assembly in 2012, though this law has some shortcomings. on similar line ,the central Govt should also make an act to give it legal basis.

DEMANDS:

· In this Budget Session itself, enact a legislation providing statutory status to the SCSP.

· Allocate 16.6 % of the Plan Outlays for the Scheduled Castes Sub Plan.

· Ensure that the allocated funds are spent for the development of Dalits and are not diverted for other general purposes.

· Ensure that the funds are spent and see that they do not lapse.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn